

- मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने अपनी पुस्तक 'वेलथ ऑफ नेशंस' में किया था? - एडम स्मिथ
- मुक्त व्यापार की स्थिति में दो देशों के बीच वस्तुओं के आदान-प्रदान में कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसके तहत घरेलू और विदेशी वस्तुओं में कोई नीतिगत विरोध होता है या नहीं? - नहीं
- प्रशुल्क-आयात अभ्यंश एवं आयात लाइसेंस, विनिमय नियंत्रण, आर्थिक अनुदान, मूल्य विभेद, सीमा शुल्क संच आदि किस व्यापारिक क्रिया के माध्यम हैं? - संरक्षण (Protection)
- किसी देश के समग्र आयातों और समग्र निर्यातों के अंतर को क्या कहा जाता है? - व्यापार शेष (Balance of trade)
- व्यापार शेष में केवल दृश्य मदों को ही सम्मिलित किया जाता है। व्यापार शेष जब प्रतिकूल होता है, तब निर्यात अधिक होगा या कम? - कम
- भारत का व्यापार शेष अब तक केवल दो वर्षों में ही अनुकूल रहा है। ये वर्ष कौन-से हैं? - वर्ष 1972-73 तथा 1976-77
- किसी देश के नागरिकों द्वारा शेष विश्व के निवासियों के साथ एक निश्चित समयावधि में किए गए सभी प्रकार के लेन-देन के विवरण को क्या कहा जाता है, जिसमें अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक दोनों प्रकार की मदों को सम्मिलित किया जाता है? - भुगतान शेष (Balance of Payment)
- भुगतान शेष में किसी देश के दृश्यगत मदों को सम्मिलित किया जाता या अदृश्यगत? - दृश्यगत और अदृश्यगत दोनों
- भुगतान शेष के खाते का निर्माण लेखांकन की रोहरी पद्धति के आधार पर किया जाता है। इसलिए यह होता है? - सदैव संतुलित
- किसी देश का दृश्यगत आयात जब उसके दृश्यगत निर्यात की तुलना में अधिक होता है, तो इन दोनों के अंतर को क्या कहा जाता है? - विदेशी व्यापार घाटा
- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने विदेशी विनिमय की समस्या के समाधान के लिए 1949 में किस समिति का गठन किया? - भोरवाला समिति
- 1950 में राजकीय व्यापार समिति की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य राजकीय क्षेत्र में व्यापार निगम की स्थापना से सम्बद्ध विभिन्न पहलुओं पर विचार करना था। राज्य व्यापार निगम की स्थापना कब की गई? - 18 मई, 1956 को
- भारतीय खनिज पदार्थों के निर्यात का विस्तार करने तथा औद्योगिक इकाइयों के लिए कच्चे माल का आयात करने के उद्देश्य 1963 में किस निगम की स्थापना की गई? - खनिज तथा धातु व्यापार निगम
- निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ: Export Processing Zone) वह औद्योगिक क्षेत्र होता है, जहां स्थापित औद्योगिक इकाइयों को रियायती दर पर अथवा बिना प्रशुल्क अदा किए कच्चा माल और पूंजीगत माल आयात करने की अनुमति होती है। भारत में इसकी अवधारणा किस वर्ष लायी गई? - वर्ष 1965
- निर्यात संवर्द्धन के लिए 1965 में भारत का ही नहीं अपितु एशिया का भी पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ) कहाँ स्थापित किया गया? - कांडला (गुजरात) में
- भारत में निजी क्षेत्र को ईपीजेड स्थापित करने की अनुमति किस वर्ष प्रदान की गई? - वर्ष 1994-95

स्वतंत्र व्यापार

स्वतंत्र व्यापार (Free Trade) वह नीति है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा देशों के मध्य वस्तुओं के आदान-प्रदान पर कोई रोक नहीं लगायी जाती है। ध्यातव्य है कि एडम स्मिथ स्वतंत्र व्यापार के जनक हैं।

मुक्त द्वार नीति

वह नीति जिसमें एक देश अन्य देशों के साथ समानता के आधार पर व्यापार करता है, मुक्त व्यापार नीति (Open door Policy) कहलाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई छिपाव नहीं होता है।

मुक्त बंदरगाह

जिस बंदरगाह पर पुनः निर्यात होने वाले सामान पर कोई कर नहीं लगाया जाता है, उसे मुक्त बंदरगाह (Free Port) कहा जाता है।

एम्बार्गो

एम्बार्गो (Embargo) से तात्पर्य व्यापार प्रतिषेध से है, जिसके अंतर्गत कोई राष्ट्र या कुछ राष्ट्र मिलकर किसी विशेष राष्ट्र के साथ अपना सम्पूर्ण व्यापार अथवा वस्तु विशेष का व्यापार निषिद्ध कर देते हैं। एम्बार्गो को घाटबंदी (नाकाबंदी) के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत कोई राष्ट्र अथवा एक से अधिक राष्ट्रों द्वारा मिलकर किसी राष्ट्र के जलयानों को किसी बंदरगाह पर रोक देता है या किसी विशेष बंदरगाह पर पहुंचने नहीं देता है।

आयात अभ्यंश

आयात अभ्यंश (Import Quota) का आशय वस्तु की उस निश्चित मात्रा अथवा मूल्य से है, जिसका आयात एक निश्चित अवधि में किया जाता है। आयात की जा सकने वाली मात्रा का निर्धारण पहले से ही कर दिया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वैदेशिक क्षेत्र

- ईपीजेड योजना के पूरक के रूप में 1981 में कौन-सा योजना प्रारम्भ की गई?
- **निर्यातोन्मुख इकाइयाँ (EOU)**
- निर्यातोन्मुख उत्पादों को बाँचागत सुविधाओं के विकास के लिए राज्यों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से अगस्त 1994 में केंद्र द्वारा कौन-सी योजना प्रारम्भ की गई?
- **निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क (EPIP)**
- ईपीआईपी योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने राज्यों को पहली बार निर्यात संवर्द्धन की प्रक्रिया में शामिल किया। भारत का पहला ईपीआईपी कहां स्थापित किया गया?
- **सीतापुर कस्बा, जयपुर जिला, राजस्थान**
- भारत में वस्तु विशेष के निर्यात संवर्द्धन के लिए स्थान विशेष पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक उत्पाद निर्यात संवर्द्धन क्षेत्र के रूप में वर्ष 1997 में किस केंद्र की स्थापना की योजना प्रारंभ की गई?
- **निर्यात विकास केंद्र (EGC)**
- विदेशी बाजारों में निर्यात सम्भावनाओं का पता लगाने, निर्यात में वृद्धि का प्रयास करने, निर्यातकर्ताओं में सहयोग स्थापित करने तथा अन्य उपलब्ध सुविधाओं को परस्पर सहयोग एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए निर्यात संवर्द्धन परिषद (EPC) की स्थापना की गई। वर्तमान में इस तरह की कितनी परिषदें कार्यरत हैं?
- **कुल 21**
- निर्यात के लिए सुदृढ़ आधारीक संरचना और सूचना उपलब्ध कराने के लिए अगस्त 1994 में व्यापार बिंदु (Trade Point) की स्थापना कहां की गई?
- **नई दिल्ली**
- कृषि एवं कृषि में संबंधित उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने एवं उनका निर्यात करने के उद्देश्य से विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की तर्ज पर आयात-निर्यात नीति 2001 के तहत वर्ष 2001-02 में किस क्षेत्र की स्थापना की गई?
- **कृषि निर्यात क्षेत्र (AEZ: Agri Export Zone)**
- भारत में वर्तमान में 60 कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना की गई है। मिर्च के क्षेत्र में एसईजेड आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थापित है। धनिया और जीरा का अलग-अलग एसईजेड किस राज्य में स्थापित है?
- **राजस्थान**
(धनिया- कोटा, बुंदी, बरान, झालावाड़ और चित्तूर; जीरा- नागौर, बाड़मेर, जालौर, पाली और जोधपुर)
- कर्नाटक भारत का पहला राज्य था जिसने 2001 में शताब्दी जैव प्रौद्योगिकी नीति बनायी। किस राज्य ने शंपूरजी पालोनजी बायोटेक पार्क के नाम से देश का पहला बायोटेक पार्क स्थापित किया?
- **आंध्र प्रदेश (समीरपेट, हैदराबाद के समीप)**
- भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) का मॉडल बहुत अधिक प्रभावी नहीं रहा, इसलिए इसकी कमियों को दूर करते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने अप्रैल 2000 में किस मॉडल को लागू किया?
- **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ: Special Economic Zone)**
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) एक ड्यूटी फ्री क्षेत्र है, जिसे केवल व्यापारिक क्रियाओं, ड्यूटी तथा टैरिफ की दृष्टि से किस क्षेत्र के रूप में लिया जाता है?
- **विदेशी क्षेत्र**
- भारत में किस ईपीजेड की छोड़कर सभी ईपीजेड को एसईजेड में बदल दिया गया है?
- **मुख्य ईपीजेड**
- एसईजेड को दो भागों में विभाजित किया जाता है- बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा एकल उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र। इन दोनों के लिए क्रमशः न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए?
- **क्रमशः 1000 हेक्टेयर तथा 100 हेक्टेयर**
- एसईजेड की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, राज्य सरकार अथवा उसकी किसी एजेंसी के माध्यम से की जा सकती है। क्या विदेशी कम्पनियां भी एसईजेड की स्थापना कर सकती हैं?
- **हां**
- एसईजेड की अवधारणा अप्रैल 2000 में लायी गई, परंतु इसे विधिक रूप से संरक्षण किस अधिनियम द्वारा दिया गया?
- **विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2006**

आयात प्रतिस्थापन

विदेश से आयातित की जाने वाली वस्तुओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उस वस्तु का देश में ही उत्पादन करना आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution) कहलाता है। आयात प्रतिस्थापन हेतु सरकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरीके अपनाती है।

अवमूल्यन

किसी मुद्रा का मूल्य किसी अन्य मुद्रा के मूल्य के सापेक्ष किसी निश्चित रणनीति के अंतर्गत कम करने की प्रक्रिया को अवमूल्यन (Devaluation) की संज्ञा प्रदान की जाती है। अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है।

कार्टेल

एक समान व्यापार में लगी फर्मों, उद्योगों तथा निगमों का ऐसा संगठन जो मूल्यों का नियंत्रण करने एवं एकाधिकारी सुविधाएं भोगने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है, को कार्टेल (Cartel) कहा जाता है।

आर्थिट्रेज

आर्थिट्रेज (Arbitrage) शब्द का प्रयोग विदेशी विनिमय के संदर्भ में किया जाता है। स्वतंत्र विदेशी बाजारों में किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर क्रय करके तुरंत ही किसी अन्य स्थान पर ऊँचे मूल्य पर बेचने की प्रक्रिया को आर्थिट्रेज कहा जाता है।

विनिमय नियंत्रण

विनिमय नियंत्रण (Exchange Control) का आशय मौद्रिक अधिकारी के उन सभी हस्तक्षेपों से होता है जो विनिमय दरों या उनसे संबंधित बाजारों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, विनिमय नियंत्रण वह सरकारी नियमन है जो विदेशी विनिमय बाजार में आर्थिक शक्तियों को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने देते हैं।

विनिमय दर

जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय की जाती है, उसे विनिमय दर (Exchange Rate) कहा जाता है।

- एसईजेड को 5 वर्षों की समयावधि के लिए निगम कर में 100 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इसके बाद के 5 वर्षों के लिए पुनर्प्रयुक्त निर्यात लाभों के लिए कितने प्रतिशत तक की छूट कंपनी लाभ कर या निगम कर में देने का प्रावधान है?

- 50 प्रतिशत

- वर्ष 1992-93 में निर्यात संवर्द्धन और भुगतान शेष खाते की प्रतिकूलता को समाप्त करने के लिए किस प्रणाली की शुरुआत की गई?

- उदारीकृत विनियम दर प्रबंधन प्रणाली (LERMS)

- लर्म प्रणाली के तहत कच्ची सामग्री संघटकों और पूंजीगत वस्तुओं सहित सभी आयातों को किस लाइसेंस के तहत कर दिया गया?

- खुला सामान्य लाइसेंस (OGL)

- अग्रिम लाइसेंस प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 1992-93 से मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस प्रणाली (Value Based Advanced License Scheme) अपनायी गई। इस प्रणाली के तहत लाइसेंस को कैसा बनाया गया?

- हस्तांतरणीय

- तृतीय पंचवर्षीय योजना तक भारत की व्यापारिक नीति आयात प्रतिस्थापना पर केंद्रित रही अर्थात् पहले केवल आयात नीति घोषित की जाती थी। 1970 में केंद्र सरकार ने किस समिति की अनुशांसा पर पहली बार निर्यात नीति की घोषणा की?

- मुदलियार समिति

- किस वर्ष के बाद से भारत में नियमित आयात तथा निर्यात नीति अलग से घोषित की जाने लगी?

- वर्ष 1970

- किस वर्ष पहली बार संयुक्त आयात-निर्यात नीति घोषित की गई, जिसमें आयातप्रतिस्थापना के साथ-साथ निर्यात संवर्द्धन पर विशेष बल दिया गया?

- वर्ष 1981 में

- वर्ष 1984 में गठित किस समिति की सिफारिशों के आधार पर 12 अप्रैल, 1985 को पहली बार त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति की घोषणा की गई?

- आखिर हुसैन समिति

- पहली त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति में पहली बार किस प्रणाली की शुरुआत कर आयात-निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाया गया?

- पास बुक प्रणाली

- उदारीकरण तथा स्वतंत्रता के मुख्य उद्देश्य के साथ भारत की पहली पंचवर्षीय निर्यात-आयात नीति कब घोषित की गई?

- अप्रैल 1992

- 31 मार्च, 1997 को वी.वी. रमैया (केंद्रीय वाणिज्य मंत्री) द्वारा भारत की दूसरी व्यापारिक पंचवर्षीय नीति घोषित की गई। इसमें किस वर्ष राजग सरकार बनने पर संशोधन किया गया?

- वर्ष 1998 में

- शुल्क पात्रता पासबुक योजना के तहत निर्यातकों को निर्यात के मूल्य पर किसी विशिष्ट प्रतिशत के आधार पर क्रेडिट राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का सूत्रपात किस व्यापारिक नीति में किया गया?

- द्वितीय पंचवर्षीय व्यापारिक नीति (1997-2002)

- 31 मार्च, 2002 को भारत की तृतीय पंचवर्षीय व्यापारिक नीति घोषित की गई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया था?

- मात्र 1 प्रतिशत

- वर्ष 1996-97 में शुरू की गई किस योजना के तहत निर्यात के लिए उत्पादन करने हेतु पूंजीगत वस्तुओं का निःशुल्क आयात करने तथा पुरानी पूंजीगत वस्तुओं को न्यूनतम कर अदा करके आयात करने की अनुमति दी गई?

- निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत योजना (EPCS)

- निर्यात संवर्द्धन के उद्देश्य से उत्पाद एवं बाजार फोकस कार्यक्रम किस वार्षिक व्यापार नीति के तहत चलाये गए?

- वार्षिक व्यापार नीति 2006-07

बहु विनियम दरें

बहु विनियम दर (Multiple Exchange Rates) प्रणाली के तहत विभिन्न दरें निर्धारित की जाती हैं। इसका उद्देश्य निर्यातों में वृद्धि तथा आयातों में कटौती करके दुर्लभ विदेशी विनियम को अधिक मात्रा में प्राप्त करना होता है। ध्यातव्य है कि बहु विनियम दर का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 में जर्मनी में किया गया था।

हेजिंग

हेजिंग से तात्पर्य होता है विभिन्न प्रकार के जोखिमों से होने वाली हानि से स्वयं को सुरक्षित रखना। विदेशी विनियम के संदर्भ इसका अर्थ निर्यात जोखिमों से सुरक्षित करना है। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिससे आयातक और निर्यातक विदेशी विनियम दरों में होने वाले उतार-चढ़ाव से उत्पन्न हानियों से स्वयं को सुरक्षित करते हैं।

व्यापार संतुलन

किसी देश के समग्र निर्यात और आयात का अंतर व्यापार संतुलन (Balance of Trade) कहलाता है। जब किसी देश का निर्यात उसके आयात की तुलना में अधिक होता है तो उस देश का व्यापार संतुलन उसके अनुकूल होता है। यदि निर्यात आयात से कम है तो व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है। ध्यातव्य है कि व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मर्दे ही सम्मिलित होते हैं।

भुगतान शेष

किसी निश्चित अवधि में किसी देश का शेष विश्व के साथ किए गए मौद्रिक लेन-देन का विवरण भुगतान शेष (Balance of Payment) कहलाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भुगतान शेष सदैव संतुलित रहता है, जबकि व्यापार शेष संतुलित अथवा असंतुलित दोनों रह सकता है। भुगतान शेष में किसी देश के दृश्यगत और अदृश्यगत दोनों मर्दों को सम्मिलित किया जाता है।

अवसर लागत

किसी वस्तु की अवसर लागत (Opportunity Cost) अगले सर्वश्रेष्ठ

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वैदेशिक क्षेत्र

निर्यात, आयात और व्यापार शेष					
वर्ष	निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) (रु. करोड़)	आयात (रु. करोड़)	व्यापार संतुलन (रु. करोड़)	परिवर्तन दर	
				निर्यात	आयात (प्रतिशत)
1950-51	606	608	-2	24.9	-1.5
1960-61	642	1122	-480	0.3	16.8
1970-71	1535	1634	-99	8.6	3.3
1980-81	6711	12549	-5838	4.6	37.3
1990-91	32553	43198	-10645	17.7	22.3
2000-01	201356	228307	-26950	26.6	5.9
2010-11	1142922	1683467	-540545	35.2	23.4
2011-12	1465959	2345463	-879504	28.3	39.3
2012-13	1634319	2669162	-1034843	11.5	13.8
2013-14	1905011	2715434	-810423	16.6	1.7
2014-15	1896348	2737087	-840738	-0.5	0.8
2015-16	1716384	2490306	-773921	-9.5	-9.0
2016-17	1849434	2577675	-728242	7.8	3.5
2017-18	1956515	3001033	-1044519	5.8	16.4
2018-19	2307726	3594675	-1286948	18.0	19.8
2018-19*	1702261	2737092	-1034831	18.5	23.6
2019-20* (अ)	1684559	2514784	-830225	-1.0	-8.1

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता। * अप्रैल-दिसंबर, अ: अनंतिम

- भारत के व्यापारिक नीति में शुरू से ही फोकस कार्यक्रम घोषित करने की परंपरा रही है। प्रथम पंचवर्षीय व्यापारिक नीति (1992-97) में राष्ट्रकूल फोकस कार्यक्रम और द्वितीय पंचवर्षीय व्यापारिक नीति (1997-2002) में लैटिन अमेरिकी फोकस कार्यक्रम का प्रावधान था। तीसरी पंचवर्षीय व्यापारिक नीति में किस पर फोकस रखा गया है?

- अफ्रीकी फोकस

- प्रथम पंचवर्षीय व्यापारिक नीति में टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सप्लोस स्कीम के तहत उन शहरों या नगरों में उत्पाद संबंधी विशेष आधारीक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था, जहां से प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपये या इससे अधिक का निर्यात होता था। इस राशि को किस वर्ष घटाकर 250 करोड़ रुपये कर दिया गया?

- वर्ष 2004-05

- वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात एवं निर्यात को सुविधापूर्वक संभव करने के लिए व्यापार से संबंधित अवस्थापना विकसित करने के उद्देश्य से व्यापार नीति (2004-09) में सरकार ने किस क्षेत्र को खोलने की घोषणा की?

- फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन्स (FTWZ)

- निर्यात के लिए आवश्यक आगंतों के आयात को सुगम बनाने हेतु एक नई शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (Duty Free Import Authorisation) योजना कब से प्रारम्भ की गई?

- 1 मई, 2006 से

- वर्ष 2009 तक विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी 1.5 प्रतिशत तक करने तथा रोजगार सृजन करने के प्रमुख उद्देश्यों के साथ भारत की प्रथम राष्ट्रीय विदेशी व्यापार नीति की घोषणा कब की गई?

- 31 अगस्त, 2004 को

विकल्प को त्यागने की लागत है। यह किसी वस्तु की लागत को मापने का एक तरीका भी है। किसी परियोजना के लागतों का पहचान करना या लागतों को जोड़ने के बजाय, कोई व्यक्ति समान रुपये खर्च करने के लिए अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प की भी पहचान कर सकता है। इस अगले सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक तरीके का लाभ मूल पसंद की अवसर लागत होता है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार

बौद्धिक सम्पदा (Intellectual Property) का अर्थ किसी डिजाइन, प्रौद्योगिकी एवं वस्तु का किसी व्यक्ति द्वारा या किसी निगम अथवा कम्पनी द्वारा आविष्कार करना है और अधिकार का अर्थ आविष्कार का किसी अन्य के द्वारा प्रयोग किए जाने पर आविष्कारक से स्वीकृति प्राप्त करना अथवा आविष्कारक को प्रतिफल लेने की वैधानिक व्यवस्था से है।

- प्रथम राष्ट्रीय विदेशी व्यापार नीति 2004-09 के तहत फलों-फूलों, सब्जियों, लघु वनोत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किस वर्ष इस योजना का विस्तार कर इसमें कुक्कुट, पशुपालन और मास्यपालन से संबंधित उत्पादों को भी शामिल कर लिया गया?

- वर्ष 2006-07

- प्रथम राष्ट्रीय विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई?

- 'सर्वट्रैड फ्रीम इंडिया' योजना

- 27 अगस्त, 2009 को तत्कालीन वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने पांच वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय राष्ट्रीय विदेशी व्यापार नीति (2009-14) की घोषणा की। इसमें किस वर्ष तक ग्लोबल व्यापार में भारत के हिस्से को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था?

- वर्ष 2020 तक

- राज्यों को निर्यात विकास हेतु उचित अधोसंरचना विकसित करने के लिए सहायता देने के उद्देश्य से असिस्टेड टू स्टेट्स फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स (ASIDE) नामक योजना शुरू की गई। किस योजना के तहत 'फोकस कंट्री तथा फोकस प्रोडक्ट' आधार पर निर्यात प्रवर्तन के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है?

- बाजार पहुँच स्कीम (MAI)

- द्वितीय राष्ट्रीय विदेशी व्यापार नीति के तहत ऐसे चयनित टाउन जो 750 करोड़ रुपये या इससे अधिक मूल्य का उत्पादन कर रहे शहरों को निर्यात विकास की सम्भाव्यता के आधार पर कौन-सा दर्जा दिया गया?

- निर्यात उत्कृष्टता के टाउन (TEE: Town with Export Excellence)

- किस स्कीम का उद्देश्य भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के चुनाव में कंछी किराया लागत तथा अन्य बाधकताओं की क्षतिपूर्ति करना है?

- फोकस मार्केट स्कीम

- किस स्कीम का उद्देश्य उन उत्पादों के निर्यात को प्रेरित करना है, जिनमें बहुत कंछी निर्यात गहनता (या/तथा) रोजगार सम्भाव्यता है, जिससे वे इन वस्तुओं के विपणन में उत्पन्न अवस्थापना संबंधी अकुशलताओं तथा सम्बद्ध लागतों का सामना कर सकें?

- फोकस प्रोडक्ट स्कीम

- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 1 अप्रैल, 2015 को भारत सरकार की पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति 2015-20 (FTP: Foreign Trade Policy) नई दिल्ली में जारी की। इस नीति में देश से वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वर्ष 2013-14 के 465.9 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2019-20 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है?

- 900 अरब डॉलर

- वर्ष 2020 तक विश्व व्यापार में भारत की व्यापार भागीदारी 2.0 प्रतिशत से बढ़ाकर कितना करने पर विचार किया गया है?

- लगभग 3.5 प्रतिशत

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

विदेशी निवेशकों द्वारा जब भौतिक सम्पदा यथा, कारखाने, भूमि, पूंजीगत वस्तुएँ तथा आधारीक संरचना वाले क्षेत्रों में निवेश किया जाता है तो इसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI: Foreign Direct Investment) कहा जाता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किया जाता है।

विदेशी ऋण

विदेशी ऋण (Foreign Debt) से आशय विदेशी सरकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिये गए ऋण से है। ऋण लेते समय दोनों देशों के मध्य निर्धारित व्याज दर तथा अन्य शर्तों एवं दशाओं के आधार पर विदेशी मुद्रा या रुपये में अदायगी की जाती है।

विदेशी सहायता

विदेशी सहायता (Foreign Assistance) का आशय पूंजी और प्राविधिक ज्ञान का रियायती शर्तों पर एक देश से दूसरे देश को हस्तांतरण से है। हस्तांतरण की यह प्रक्रिया विश्व पूंजी बाजार और श्रम बाजार में प्रचलित शर्तों से आसान शर्तों पर होती है।

सीमा शुल्क क्षेत्र

सीमा शुल्क क्षेत्र (Custom Area) वह भौगोलिक क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं का आवागमन बिना किसी तटकर के होता है। इसमें न केवल एक देश का ही क्षेत्र सम्मिलित होता है, बल्कि उस पर निर्भर दूरगामी क्षेत्र भी सम्मिलित होते हैं। सीमा शुल्क क्षेत्र में दो या दो से अधिक देश भी सम्मिलित हो सकते हैं। इन्हें सीमा शुल्क संघ (Custom Union) की संज्ञा प्रदान की जाती है।

पण्य निर्यात, आयात और पीओएल का कुल आयात में हिस्सा

वर्ष	2009-14	2014-19	2018-19	2019-20H ¹
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पण्य निर्यात	15.7	12.7	12.1	11.3
गैर-पीओएल निर्यातों में वृद्धि	11.0	2.6	6.6	-0.8*
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पण्य आयात	24.3	18.7	18.9	17.6
कुल आयात में पीओएल का हिस्सा (%)	32.1	25.2	27.4	26.3

स्रोत: आर्थिक समीक्षा 2019-20; वाणिज्य विभाग एवं केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय; *अप्रैल-दिसंबर; H¹: प्रथम छमाही

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वैदेशिक क्षेत्र

- देश का निर्यात बढ़ाने के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 में किस प्रकार का मिशन स्थापित करने पर बल दिया गया है, जो निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ एक संस्थागत ढांचे का काम करेगा? - निर्यात संवर्द्धन मिशन
- विदेश व्यापार नीति की वार्षिक समीक्षा के बजाय अब पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति की 2.5 वर्ष में समीक्षा की जाएगी। पहले इसकी समीक्षा कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती थी? - प्रति वर्ष
- विदेश व्यापार नीति (2015-20) में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार बढ़ाने के लिए किन दो योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की गई है? - भारत वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) और भारत सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस)
- वैश्विक मंदी ने वर्ष 2019 की प्रारंभ से ही उन्नत राष्ट्रों को उदार मौद्रिक नीति अपनाने को बाध्य किया है। इस मंदी का एक प्रमुख कारण अमेरिका-चीन व्यापार तनाव रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक 2018 में विश्व उत्पादन में वृद्धि 3.6 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2019 में कम होकर कितनी प्रतिशत हो गई? - मात्र 3.3 प्रतिशत
- विश्व व्यापार में भी वर्ष 2018 में मंदी देखी गई। वर्ष 2017 में विश्व व्यापार में वृद्धि जहाँ 4.6 प्रतिशत की दर से हुई, वही 2018 में यह कम होकर कितनी हो गई? - लगभग 3.0 प्रतिशत
- अप्रैल-दिसंबर 2018-19 के दौरान भारत का चालू खाता घाटा गत वर्ष 35.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.8 प्रतिशत) की तुलना में 51.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 2.6 प्रतिशत) रहा। इस चालू खाता घाटा का प्रमुख कारण क्या था? - अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि
- अप्रैल-दिसंबर 2018-19 के दौरान व्यापार घाटा पिछले वर्ष की संगत अवधि के 118.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर कितना हो गया? - 145.3 बिलियन डॉलर
- चालू खाता घाटे में प्रत्याशित वृद्धि वस्तु व्यापार घाटे में वृद्धि से प्रेरित है जोकि जीडीपी के अनुपातिक रूप में 2016-17 में 4.9 प्रतिशत से 2017-18 में 6.0 प्रतिशत तक बढ़ गई। वर्ष 2018-19 में यह अनुपात कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? - मात्र 6.7 प्रतिशत

बहुराष्ट्रीय निगम

एक ऐसी कम्पनी, जिसका कार्यक्षेत्र एक से अधिक देशों में होता है और जिसका उत्पादन एवं सेवा सुविधाएँ उस देश के बाहर भी सम्पन्न होती हैं, जहाँ इसका जन्म हुआ होता है, को बहुराष्ट्रीय निगम (Multinational Corporation) कहा जाता है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार, उस कम्पनी को बहुराष्ट्रीय निगम माना जाना चाहिए जो दूसरे देशों से अपने राजस्व का 25% या उससे अधिक प्राप्त करे। एक अनुमान के मुताबिक विश्व की 10% कम्पनियों के पास 80% से अधिक का मुनाफा है।

निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति

अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (IIP: International Investment Position) एक सांख्यिकीय विवरण है जो एक समय में अर्थव्यवस्था के निवासियों की वित्तीय आस्तियों जो अनिवासियों पर दावे अथवा आरक्षित आस्तियों के रूप में रखे गए स्वर्ण विलियन हैं; अर्थव्यवस्था के निवासियों तथा गैर निवासियों (आईएमएफ) की देनदारियों के मूल्य को दर्शाता है। आस्तियों और देनदारियों में अंतर आईआईपी में निवल स्थिति का है और यह शेष विश्व के निवल दावे या निवल देनदारियों को प्रस्तुत करता है। धनात्मक एनआईआईपी (Net International Investment Position) मूल्य एक लेनदार देश को दर्शाता है, जबकि ऋणात्मक मूल्य कर्जदार देश को दर्शाता है।

2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में निर्यातों एवं आयातों की पण्यवार रचना (प्रतिशत हिस्सा के रूप में)

रैंक	निर्यातित वस्तुएं	%हिस्सा*	रैंक	आयातित वस्तुएं	%हिस्सा**
1.	पेट्रोलियम उत्पाद	13.7	1.	अपरिष्कृत पेट्रोलियम	21.0
2.	मोती, मूल्यवान, अर्ध मूल्यवान पत्थर	7.0	2.	स्वर्ण	6.4
3.	औषधि निर्माण आदि	5.0	3.	पेट्रोलियम उत्पाद	5.6
4.	स्वर्ण व अन्य मूल्यवान धात्विक आभूषण	4.5	4.	कोयला, कोक और बिक्रेट आदि	4.8
5.	लोहा एवं इस्पात	3.0	5.	मोती, मूल्यवान, अर्ध मूल्यवान पत्थर	4.6
6.	बिजली मशीनरी एवं उपकरण	2.8	6.	इलेक्ट्रॉनिक घटक	3.6
7.	जैविक रसायन	2.8	7.	दूरसंचार उपकरण	3.2
8.	कपड़ा अन्य सामान सहित	2.6	8.	जैविक रसायन	2.7
9.	मोटर वाहन एवं कार	2.5	9.	डेरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	2.6
10.	समुद्री उत्पाद	2.3	10.	लोहा एवं इस्पात	2.5

स्रोत: वाणिज्यिक विभाग; आर्थिक समीक्षा 2019-20; *कुल निर्यात में प्रतिशत हिस्सा; **कुल आयात में प्रतिशत हिस्सा

- वस्तु निर्यात एवं वस्तु आयात दोनों की वृद्धि 2016-17 से 2017-18 तक तेजी से बढ़ी थी। इसके बाद वस्तु निर्यात की वार्षिक वृद्धि 2017-18 में 10 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2018-19 में कितनी हो गई? - **मात्र 8.8 प्रतिशत**
- वस्तु आयात की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2017-18 में 21.0% से घटकर वर्ष 2018-19 में कितनी रह गई? - **मात्र 10.4 प्रतिशत**
- वस्तु निर्यात में वृद्धि वर्ष 2016-17 में 5.2% से 2018-19 में 8.8% तक मुख्य रूप से पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल) निर्यात में उच्च वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई। पीओएल निर्यात की वृद्धि दर 2016-17 में 3.1 प्रतिशत थी, जो 2018-19 में बढ़कर कितनी हो गई? - **लगभग 24.2%**
- विश्व बैंक के अप्रैल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक भारत वर्ष 2018 में सर्वाधिक प्रेषित धन प्राप्तकर्ता (Remittance Receiver) देश रहा। इस वर्ष भारतीयों ने कितना धन अपने देश भेजा? - **78.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर** (इस मामले में भारत के बाद क्रमशः चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र का स्थान रहा।)
- वर्ष 2017-18 में विदेशी मुद्रा भंडार 424545 यूएस मिलियन डॉलर था, जो वर्ष 2018-19 में कम होकर कितना हो गया? - **412871 मिलियन डॉलर**
- भारत विश्व के सभी देशों के बीच आठवां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। चालू खाता घाटे पर चलने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं (यथा- अमेरिका, यूके, तुर्की, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, इंडोनेशिया और फ्रांस) के बीच भारत किस स्थान का विदेशी मुद्रा भंडार धारक है? - **सबसे बड़ा**
- भारत का विदेशी ऋण मार्च 2018 के अंत पर इसके स्तर से 1.6 प्रतिशत की कमी के साथ दिसंबर 2018 के अंत तक 521.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। मार्च अंत 2018 की तुलना में दिसंबर 2018 के अंत में दीर्घावधि ऋण कितना था? - **417.3 बिलियन डॉलर (कुल विदेशी ऋण का 80.1%)**
- विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार यद्यपि भारत विकासशील देशों (चीन और ब्राजील के पश्चात) में तीसरा बड़ा कर्जदार देश (कुल राशि में) है, लेकिन कुल ऋणों में लघु अवधि ऋण का अनुपात केवल लगभग 19.0 प्रतिशत होने के कारण इसके ऋण की औसत अवधि बहुत अधिक है। चीन में कुल ऋणों में लघु अवधि ऋण का अनुपात कितना है? - **लगभग 69%**

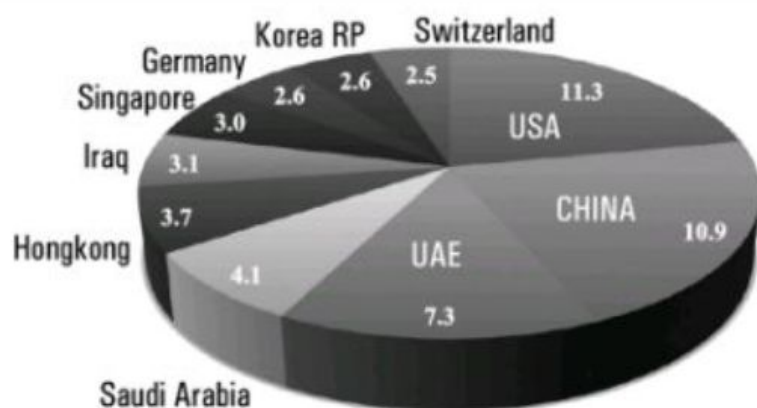
आरईईआर

आरईईआर (Real Effective Exchange Rate) का ह्रास यह इंगित करता है कि भारत के निर्यातों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मकता हो जाना चाहिए था, परंतु आरईईआर में वृद्धि कम प्रतिस्पर्धात्मक निर्यातों को दर्शाता है। निर्यातों की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता इस बात को देखकर बेहतर रूप से आंकी जा सकती है कि एक समय अवधि में व्यापार की शर्तें कैसी रही हैं। वस्तु अथवा किसी देश के व्यापार की निवल शर्तें आधारवर्ष के सापेक्ष सापेक्ष गए निर्यात के इकाई मूल्य तथा आयात के संगत इकाई मूल्य का अनुपात है। अगर यह अनुपात बढ़ता है, तो यह दर्शाता है कि देश, जो निर्यातों की प्रत्येक इकाई के लिए आयातों का विनिमय करता है, तुलनात्मक रूप से अधिक प्राप्त कर रहा है और यदि यह अनुपात घटता है तो देश तुलनात्मक रूप से कम प्राप्त कर रहा है।

जीटीटी और आईटीटी

व्यापार की शर्तों के सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले दो अन्य सूचकांक हैं- व्यापार की सकल शर्तें (GTT: Gross Terms of Trade) और व्यापार की आय संबंधी शर्तें (ITT: Income Terms of Trade) हैं। जीटीटी किसी देश के आयातों एवं निर्यातों की कुल मात्रा का अनुपात है, जबकि आईटीटी आयातों के इकाई मूल्य

2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में भारत के सबसे बड़े 10 व्यापारिक भागीदार (प्रतिशत में)



- वर्ष 2019-20 के दौरान भारत के सबसे बड़े 10 व्यापारिक भागीदारों का भारत के कुल पण्य व्यापार में 50 प्रतिशत से अधिक योगदान है।
- भारत 2014-15 से लगातार दो सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार अधिशेष कर रहा है।
- भारत का अन्य बड़े व्यापारिक भागीदारों, जैसे- चीन, यूएई, इराक, जर्मनी, कोरिया, इंडोनेशिया और स्विट्जरलैंड के साथ 2014-15 से लगातार व्यापार घाटा हो रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वैदेशिक क्षेत्र

- वर्ष 2017-18 में किस उत्पाद का देश के मूल्य के हिसाब से निर्यात अंश में सर्वाधिक योगदान 14.1% रहा?
- **पेट्रोलियम उत्पाद**
(2018-19 में जैविक रसायनों के निर्यात में सबसे ज्यादा वृद्धि 30.6% देखी गई।)
- वर्ष 2018-19 में कुल आयात में स्वर्ण और अर्ध-मूल्यवान धातु के आभूषणों का हिस्सा 6.4 प्रतिशत (दूसरा) तथा मोती/अर्धमूल्यवान पत्थरों का हिस्सा 5.3 प्रतिशत (तीसरा) था। इस अवधि में कुल आयात में 22.2 प्रतिशत का सर्वाधिक हिस्सा किसका रहा?
- **पेट्रोलियम: कच्चा माल**
- वर्ष 2018-19 के दौरान भारत के आयात में किस मद में सबसे अधिक 54.6% की बढ़ोतरी देखी गई?
- **इलेक्ट्रॉनिक्स घटक**
- संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सर्वाधिक निर्यातोन्मुख देश बना हुआ है जो वर्ष 2018-19 में भारत के निर्यात का (मूल्य के अर्थ में) 16% अंश के लिए उत्तरदायी है। अमेरिका के बाद आने वाले तीन देश कौन हैं?
- **संयुक्त अरब अमीरात (9.1%), चीन (5.1%) और हांगकांग (3.9%)**
- वर्ष 2018-19 में भारतीय निर्यात में सर्वाधिक बढ़ोतरी किस देश को किए गए निर्यात में देखी गई?
- **नीदरलैंड (40.7 प्रतिशत)**
(इसके बाद 25.6 प्रतिशत के साथ चीन और 17.4 प्रतिशत के साथ नेपाल का स्थान रहा)
- चीन भारत के आयातों का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है जो 2018-19 में कुल आयातित मूल्य के 13.7% के लिए जिम्मेदार है (बाद के क्रमशः अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब)। लेकिन सबसे ज्यादा 118.1% की वृद्धि किस देश से किए गए आयात में देखी गई?
- **सिंगापुर**
- वाणिज्यिक व्यापार घाटा के वित्तपोषण में निवल सेवाओं का योगदान 2016-17 में 62.2 प्रतिशत था, जो 2018-19 में घटकर कितना हो गया? - **मात्र 43.7 प्रतिशत**
- कुल देनदारियों एवं जीडीपी का अनुपात, ऋण और गैर ऋण घटक दोनों को मिलाकर वर्ष 2015 के 43 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018 में कितना प्रतिशत मापा गया?
- **लगभग 38 प्रतिशत**



द्वारा विभाजित निर्यातों का मूल्य है जो यह दर्शाता है कि आयातों के संबंध में किसी देश की क्रयशक्ति कितनी बेहतर अथवा खराब हो गई है। विकासशील देशों के लिए आईटीटी सर्वाधिक संगत संकेतक रही है, क्योंकि ये आयात को अपनी क्षमता में परिवर्तनों के बारे में अधिक चिंतित है। विशेष रूप से तब जब ये वस्तु आयातों पर ज्यादा निर्भर होती है, जैसे- भारत कच्चे तेल के आयातों पर निर्भर रहा है।

राजकीय ई-बाजार

राजकीय ई-बाजार (GEM) एक मापन प्रणाली है तथा वह पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी एवं व्यवस्था संचालित होने के साथ

द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष/घाटा (वर्ष 2018-19 से दिए गए) (मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर)						
देश	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
व्यापार अधिशेष देश						
संयुक्त राज्य अमेरिका	20.63	18.55	19.90	21.27	16.86	10.91
संयुक्त अरब अमीरात	6.89	10.87	9.67	6.41	0.34	0.25
व्यापार घाटा देश						
चीन पीआरपी	-48.48	-52.70	-51.11	-63.05	-53.57	-35.32
सऊदी अरब	-16.95	-13.94	-14.86	-16.66	-22.92	-14.32
इराक	-13.42	-9.83	-10.60	-16.15	-20.58	-13.98
जर्मनी	-5.25	-5.00	-4.40	-4.61	-6.26	-3.09
कोरिया आरपी	-8.93	-9.52	-8.34	-11.90	-12.05	-7.80
इंडोनेशिया	-10.96	-10.31	-9.94	-12.48	-10.57	-6.99
स्विट्जरलैण्ड	-21.06	-18.32	-16.27	-17.84	-16.90	-11.97
हांगकांग	8.03	6.04	5.84	4.01	-4.99	-3.88
सिंगापुर	2.68	0.41	2.48	2.74	-4.71	-3.15

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता अ: अर्न्तम * अप्रैल-नवंबर

विदेशी मुद्रा भंडार (यूएस मिलियन डॉलर)					
वित्त वर्ष की समाप्ति	सोना	आरटीपी	एसडीआर	वि. प्रा. भं.	कुल
1950-51	247	--	--	1914	2161
1960-61	247	--	--	390	637
1970-71	243	--	148	584	975
1980-81	370	--	603	5850	6823
1990-91	3496	--	102	2236	5834
2001-02	3047	--	10	51049	54106
2010-11	22972	2947	4569	274330	304818
2011-12	27023	2836	4469	260069	294397
2012-13	25692	2301	4328	259726	292046
2013-14	21567	1834	4464	276359	304223
2014-15	19038	1292	3985	317324	341638
2015-16	20115	2456	1502	336104	360176
2016-17	19869	2321	1446	346319	369955
2017-18	21484	2079	1540	399442	424545
2018-19	23071	2986	1457	385357	412871

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक समीक्षा 2019-20;
एसडीआर: विशेष आहरण अधिकार; **आरटीपी:** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित ट्रांश स्थिति; **वि. प्रा. भं.:** विदेशी प्रारक्षित भंडार

- कुल देनदारियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का हिस्सा बढ़ा है, जबकि किस प्रकार के निवेश का हिस्सा घटा है?
- निवल पोर्टफोलियो निवेश
 (यह स्थिति चालू खाता घाटा वित्त पोषण के बढ़ते स्थायी साधनों के स्वरूप को प्रदर्शित करती है।)
- भारतीय रुपये ने वर्ष 2017-18 में 65-68 प्रति अमेरिकी डॉलर के बीच में कारोबार किया था, परंतु वर्ष 2018-19 में यह गिरकर कितना तक पहुंच गया?
- 70-74 अमेरिकी डॉलर के बीच
- भारत ने विभिन्न देशों/देशों के समूह के साथ 28 द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कारोबार करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। 2018-19 में भारत का ऐसे देशों के साथ निर्यात 121.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो सभी देशों को भारत के निर्यात का कितना है?
- मात्र 36.9 प्रतिशत
- वर्ष 2018-19 में ही भारत का ऐसे देशों से आयात, जिनके साथ इसका कारोबार करार है, 266.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। यह भारत के सभी देशों से आयात का कितना प्रतिशत बैठता है?
- करीब 52.0 प्रतिशत
- भारत के विदेश विनिमय रिजर्व में विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति (FCA), स्वर्ण और आईएमएफ में आरटीपी (Reserve Tranche Position) के अलावा और क्या शामिल किया जाता है?
- विशेष आहरण अधिकार पत्र (SDR)
- भारत में विदेशी ऋण को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है- अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विदेशी ऋण। अल्पकालीन ऋणों की अदायगी 3 से 5 वर्ष के अंदर तथा दीर्घकालीन ऋणों की अदायगी 5 से 20 वर्षों में की जाती है। द्विपक्षीय सहायता, बहुपक्षीय सहायता, आईएमएफ ऋण, निर्यात ऋण, वाणिज्यिक ऋण, अनिवासी भारतीय जमाएं और रुपया ऋण किस प्रकार के ऋण हैं?
- दीर्घकालीन ऋण

ही वस्तुओं और सेवाओं की सरलता, कुशलता एवं तीव्रता से आपूर्ति करती है। इस पोर्टल को अगस्त 2016 में शुरू किया गया, जो अक्टूबर 2016 तक पूरी तरह सक्रिय हो गया। वर्ष 2018 में 4.44 लाख से अधिक उत्पाद एवं सेवाएं, करीब 71,700 आपूर्तिकर्ता और 16,000 से अधिक क्रेता संगठन जीईएम का अंग बन चुके हैं।

चक्रदार ऋण/रिवाल्विंग क्रेडिट

रिवाल्विंग क्रेडिट (Revolving Credit or Debt), एक प्रकार का लाइन ऑफ़ क्रेडिट है जहां ग्राहक पैसे उधार लेने के लिए वित्तीय संस्थान के लिए एक प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान करता है और फिर जरूरत पड़ने पर धन का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। यह आमतौर पर परिचालन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है और प्रत्येक माह ग्राहक की वर्तमान नकदी प्रवाह की जरूरतों के आधार पर निकाली गई राशि में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वैदेशिक क्षेत्र

भारत का वक्राया विदेशी ऋण (अमेरिकी मिलियन डॉलर)									
ऋण संघटक	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
बहुपक्षीय	48475	50452	51590	53418	52391	54000	54502	57249	57454
द्विपक्षीय	25712	26884	25158	24727	21726	22464	23210	25382	25622
आईएमएफ*	6308	6163	5964	6149	5488	5605	5410	5784	5523
निर्यात ऋण	18647	18990	17760	15518	12608	10640	9609	9483	7944
वाणिज्यिक उधार	100476	120136	140125	149375	180295	180761	172358	201826	206650
एनआरआई**	51682	58608	70822	103845	115163	126929	116867	126182	130423
रुपया ऋण	1601	1354	1258	1468	1506	1278	1228	1213	1158
कुल दीर्घकालिक ऋण	252901	282587	312677	354500	389177	401677	383184	427117	434774
अल्पावधि ऋण	64990	78179	96697	91678	85498	83375	88124	102173	108415
कुल जोड़	317891	360766	409374	446178	474675	485052	471308	529290	543189
रियायती ऋण***	47499	48063	45518	46454	41916	43526	44077	48324	47467
कुल विदेशी ऋण में									
रियायती ऋण (%)	14.9	13.3	11.1	10.4	8.8	9.0	9.4	9.1	8.7
कुल विदेशी ऋण में									
अल्पावधि ऋण (%)	20.4	21.7	23.6	20.6	18.0	17.2	18.7	19.3	20.0

स्रोत: वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), रक्षा मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
 * मार्च 2004 से आगे आवॉटेंट एसडीआर से संबंधित ** 1 वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली; इन आंकड़ों में उपा. र्जित व्याज शामिल है। *** रूस से लिया गया एवं निर्यातों के माध्यम से भुगतान किया जाने वाला रुपया मूल्यवर्गित ऋण सभी आंकड़ें मार्च अंत के हैं।

- जब किसी देश द्वारा सुनियोजित रुपनीति को ध्यान में रखकर अपनी मुद्रा का, किसी देश की मुद्रा अथवा कुछ मुद्राओं के समूह के सापेक्ष उसकी कीमत में कमी की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है?
- अवमूल्यन (Devaluation)
- मुद्रा का अवमूल्यन करने से निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- बढ़ता है
- अवमूल्यन की सफलता निर्यात और आयात की मूल्य मांग की लोच पर निर्भर करती है। इसे किस दशा के नाम से जाना जाता है?
- मार्शल लर्नर दशा
- भारतीय मुद्रा रुपये का अब तक तीन बार अवमूल्यन किया गया। ये अवमूल्यन कब-कब किए गए?
- 1949, जून 1966 और जुलाई 1991
- अवमूल्यन की स्थिति में किस दर में कमी हो जाने के कारण निर्यात सस्ता हो जाता है और निर्यात तेजी से बढ़ता है?
- विनिमय दर
- एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की दर को क्या कहा जाता है?
- विदेशी विनिमय दर
- दो मुद्राओं की विनिमय दर में परिवर्तन होने से एक मुद्रा की विनिमय दर में कमी होना क्या कहलाता है?
- मूल्य ह्रास
- जब किसी मुद्रा की मांग अधिक एवं पूर्ति कम होती है तो इस स्थिति में मुद्रा का अधिमूल्यन होता है। अधिमूल्यन की स्थिति में किसी मुद्रा का क्रय-विक्रय भविष्य में लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। अधिमूल्यन की स्थिति में निर्यात पर कैसा प्रभाव पड़ता है?
- नकारात्मक
- जब विधिमान्य तरीके से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के शत-प्रतिशत भाग को खुले बाजार में प्रचलित दर पर घरेलू मुद्रा में बदलने की अनुमति होती है, तो उसे क्या कहा जाता है?
- मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता

मार्शल लर्नर दशा

अवमूल्यन की सफलता निर्यात और आयात की मूल्य मांग की लोच पर निर्भर करती है, जिसे मार्शल लर्नर दशा कहा जाता है। इसके मुताबिक अवमूल्यन तभी सफल होगा जबकि अवमूल्यन करने वाले देश के निर्यात की मूल्य मांग की लोच तथा उसकी आयात की मूल्य मांग की लोच का योग 1 से अधिक हो। यदि इसका योग 1 से कम हो तो अवमूल्यन के बाद भुगतान संतुलन और प्रतिकूल होगा और यदि वह 1 के बराबर हो तो अवमूल्यन का भुगतान संतुलन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होगा।

लेटर ऑफ अंडरटेकिंग

लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) एक तरह की गारंटी होती है, जिसे एक बैंक दूसरे बैंक को जारी करता है, जिसके आधार पर दूसरे बैंक अकाउंट होल्डर को पैसा मुहैया कराते हैं। एलओयू सिक्कोर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म स्विफ्ट के जरिए एक मैसेज के

भुगतान शेष: सार (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)						
मद/वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 (अप्रै.-सित)	2019-20 (अप्रै.-सित)
I. चालू खाता						
(i) निर्यात	2,66,365	2,80,138	3,08,970	3,37,237	1,66,788	1,62,743
(ii) आयात	3,96,444	3,92,580	4,69,006	5,17,519	2,62,575	2,47,037
(iii) व्यापार संतुलन	-1,30,079	-1,12,442	-1,60,036	-1,80,283	-95,788	-84,294
(iv) अदृश्य (निवल)	1,07,928	98,026	1,11,319	1,23,026	60,931	63,673
(क) सेवाएं	69,676	68,345	77,562	81,941	38,932	40,474
(ख) आय	-24,375	-26,302	-28,681	-28,861	-14,363	-14,739
(ग) अंतरण	62,627	55,983	62,438	69,946	36,362	37,938
चालू खाता शेष	-22,151	-14,417	-48,717	-57,256	-34,857	-20,621
II. पूंजी खाता						
(i) विदेशी सहायता	1,505	2,013	2,944	3,413	478	1,913
(ii) विदेशी वाणिज्यिक उधार (निवल)	-4,529	-6,102	-183	10,416	877	9,767
(iii) अल्कालिक ऋण	-1,610	6,467	13,900	2,021	1,298	1344
(iv) बैंकिंग पूंजी जिसका अनिवासी जमा	10,630	-16,616	16,190	7,433	10,583	-5,702
(v) विदेशी निवेश (निवल)	31,891	43,224	52,401	30,094	9,040	28,646
(क) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	36,021	35,612	30,286	30,712	16,983	21,327
(ख) पोर्टफोलियो निवेश	-4,130	7,612	22,115	-618	-7,943	7,319
(vi) अन्य प्रवाह	3,242	7,460	6,138	1,026	-885	3967
कुल पूंजी खाता शेष	41,128	36,447	91,390	54,403	21,391	39,935
III. भूल-चूक सहित	-1,073	-480	902	-486	259	-211
IV. समग्र शेष	17,905	21,550	43,574	-3,339	-13,206	19102
V. प्रारक्षित निधि में परिवर्तन	-17,905	-21,550	-43,574	3,339	13,206	-19,102
(+) बढ़त को दर्शाता है (-) घटत को दर्शाता है स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक समीक्षा 2019-20						

- भारत का लॉजिस्टिक्स उद्योग वर्तमान में लगभग 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास होने का अनुमान है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक के अनुसार, समग्र लॉजिस्टिक्स निष्पादन में भारत की रैंकिंग में उछाल आया है। वर्ष 2018 में इस सूचकांक में भारत का कौन-सा स्थान रहा? **- 44वां स्थान**
- 1992-93 में व्यापार खाते में रुपये को आंशिक परिवर्तनीय बनाने के साथ-साथ भारत में दोहरी विनियम दर नियंत्रण प्रणाली लागू की गई। वर्ष 1993-94 में किस खाते में रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया, जिसके साथ ही दोहरी विनियम नियंत्रण व्यवस्था समाप्त हो गई? **- व्यापार खाते में**
- वर्ष 1993-94 से भारत में एकीकृत विनियम दर प्रबंध प्रणाली लागू की गई। चालू खाते में रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय किस वर्ष बनाया गया? **- वर्ष 1994-95**
- पूंजीगत खाता में रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के लिए सुझाव देने हेतु पहली बार वर्ष 1997 में किस समिति का गठन किया गया? **- तारापोर समिति**
- पूंजीगत खाता में रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के लिए सुझाव देने के लिए दूसरी बार तारापोर समिति का गठन कब किया गया? **- वर्ष 2006 में**

रूप में भेजा जाता है। स्विफ्ट के जरिए ऐसे ट्रांसफर करने के संदेश को वैल्यू बैंक द्वारा दूसरे पक्ष को जारी एक डिमांड ड्राफ्ट के बराबर होती है। एलआंवु एक तरह की बैंक गारंटी होती है, जो ओवरसीज इम्पोर्ट पेमेंट के लिए जारी की जाती है। उल्लेखनीय है कि यह टर्म पीएनबी घोटाले के बाद काफी प्रचलित हुआ था।

लाइन ऑफ क्रेडिट

लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) वित्तीय संस्थान, सामान्यतः बैंक और ग्राहक के बीच एक व्यवस्था है, जिसके तहत ग्राहक अधिकतम

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वैदेशिक क्षेत्र

- वर्तमान समय में भारत में सिकर चालू खाते में रुपया पूरी तरह से परिवर्तनीय है। पूंजीगत खाते में परिवर्तनीयता कैसी है?
- आंशिक
- द्वितीय तारापोर समिति ने अगस्त 2006 को दी गई अपनी रिपोर्ट में पूंजीगत खाते में रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के लिए तीन चरणीय कार्यक्रम निर्धारित किया। ये तीन चरण कौन हैं?

- पहला चरण (2006-07), दूसरा चरण (2007-09) तथा तीसरा चरण (2009-11)

- विशेष आहरण अधिकार (SDR: Special Drawing Right) आईएमएफ द्वारा सृजित एक प्रकार की मुद्रा है जो सदस्य देशों के बीच बिना किसी भौतिक हस्तांतरण के परस्पर भुगतान के लिए स्वीकार की जाती है। इसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ?

- 1970

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने किस देश के साथ मिलकर शारजाह में समुद्री मोती विकसित करने के लिए एक परियोजना प्रारंभ की है?

- संयुक्त अरब अमीरात

- जनवरी 1982 में स्थापित भारतीय आयात-निर्यात बैंक (Exim Bank) नए बाजारों विशेषकर दक्षिण अफ्रीका, सीआईएस देशों एवं लैटिन अमेरिका में देश का निर्यात बढ़ाने के लिए किस प्रकार के ऋण की अवधारणा पर कार्य कर रहा है?

- चक्रवर्त ऋण (Revolving Debt)

- जुलाई 1957 में स्थापित निर्यात ऋण देने वाली उस एजेंसी का क्या नाम है, जिसका नियंत्रण वाणिज्य मंत्रालय के पास है और जिसके कार्यक्षेत्र में लगभग 20,000 निर्यातक हैं, जिनमें से 85 प्रतिशत एमएसएमई हैं?

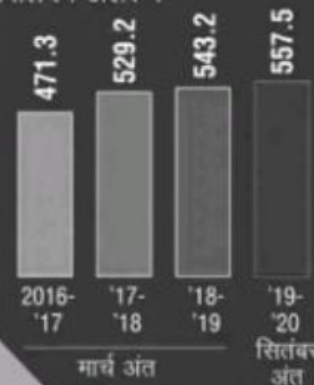
- भारतीय निर्यात ऋण प्रतिभूति गारंटी निगम (ECGC)

आर्थिक
समीक्षा

2019-20

ऋण का बोझ

भारत पर विदेशी ऋण,
विलियन डॉलर में



ऋण राशि प्राप्त कर सकता है। बैंक किसी भी समय इस व्यवस्था के तहत दिए गए ऋण या धन की समीक्षा कर सकता है और इस बात को सुनिश्चित कर सकता है कि ऋण समझौते में निर्धारित अधिकतम राशि या क्रेडिट लिमिट से अधिक न हो। साथ ही, बैंक समय-समय पर न्यूनतम भुगतान करने जैसी किसी शर्त को पूरा भी कर सकता है।

जनरल एंटी एवॉयडेंस रूल्स (गार)

जनरल एंटी एवॉयडेंस रूल (गार) कर चोरी और कालेधन पर रोक लगाने के लिए बनाये गए प्रावधानों का एक समुच्चय है। इसके तहत देश में विदेशी कंपनियों द्वारा किए जा रहे निवेश या समझौतों को कर नियमों के दायरे में लाना है। तात्पर्य यह है कि गार का उद्देश्य कंपनियों को केवल टैक्स से बचने के लिए सौदे दूसरे देशों के रास्ते करने से रोकना है। इसके अलावा सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी और कर व्यवस्था को खामियां दूर करना भी इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। भारत में 2010 में गार को प्रत्यक्ष कर संहिता में प्रस्तावित किया गया था। फिर वर्ष 2012-13 के बजट में इसके प्रावधानों का उल्लेख किया गया। अंततः 1 अप्रैल, 2017 से इसको लागू किए जाने का फैसला किया गया।

भारतीय निर्यात एवं आयात की स्थिति

पेट्रोलियम (पीओएल) निर्यातों का भारत के निर्यात पण्यों में बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तथापि, चूंकि पेट्रोलियम निर्यात पेट्रोलियम आयातों का एक मूल्य संबर्द्धन मंद है, अतः पीओएल निर्यातों में से शुद्ध निर्यात यह दर्शाता है कि विदेशों से होने वाले भारत के निर्यात से देश में कितना मूल्य संबर्द्धन प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2009-14 से 2014-19 तक गैर-पीओएल निर्यातों में वृद्धि में काफी गिरावट आई है। 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में मूल्य के संदर्भ में पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे अधिक निर्यात होना जारी रहा। वृद्धि के संदर्भ में, औषध-यौगिकों, जैवचदार्थों में 2011-12 और 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के बीच सबसे अधिक वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में भारत से सबसे अधिक निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ, जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), चीन और हांगकांग आते हैं। वर्ष 2011-12 और 2019-20 के बीच यूएसए भारत से होने वाले सबसे अधिक निर्यात वाला देश हो गया।

पण्य आयात/सकल घरेलू अनुपात में वृद्धि का भुगतान शेष की स्थिति पर निवल ऋणात्मक प्रभाव होता है। कई वर्षों से भारत में इस अनुपात में गिरावट आ रही है जो भुगतान शेष की स्थिति पर निवल सकारात्मक प्रभाव को सूचित करता है। आयात समूह में कच्चे तेल के आयात का बहुत अधिक हिस्सा है। जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो कुल आयात में कच्चे तेल का अंश भी बढ़ता है जिससे सकल घरेलू उत्पाद के साथ आयात के अनुपात में वृद्धि होती है। वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के आयात बास्केट में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे बड़ा अंश था। इसके बाद सोना एवं पेट्रोलियम उत्पाद आते हैं। यद्यपि वर्ष 2011-12 एवं 2019-20 के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का आयात नगण्य श्रेय से तेजी से बढ़कर 3.6% हो गया। चीन भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई एवं सउदी अरब आते हैं। हाल ही में हांगकांग, कोरिया एवं सिंगापुर भी भारत के लिए महत्वपूर्ण आयात स्रोत के रूप में उभरे हैं।